



राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन

बीसवीं सदी के दौरान औपनिवेशिक शासन के अधीन रहनेवाले लाखों लोग प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय स्वतंत्रता-संग्राम में संलग्न थे। 1945 से 1980 के बीच एशिया, अफ्रीका, ओशियाना (पश्चिमी प्रशांत महासागर में बसे द्वीप) और कैरिबियाई देशों के प्रायः समस्त भाग, जो यूरोपीय, जापानी और अमेरिकी शासन के अधीन थे, स्वतंत्र हो चुके थे और स्वयं को स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में संगठित कर चुके थे।

दूसरे विश्वयुद्ध (1939-1945) के दौरान, पराजित शक्तियाँ जर्मनी एवं जापान के साम्राज्यवादी और विस्तारवादी लक्ष्य विफल कर दिए गए। यहां तक कि ब्रिटेन, फ्रांस और नीदरलैंड जैसी विजयी औपनिवेशिक ताकतें भी अपनी साम्राज्यवादी प्रतिबद्धताएं पूरी करने में असमर्थ रहीं और उनके नेताओं पर 'विउपनिवेशीकरण' अर्थात् औपनिवेशिक शासन समाप्त करने का दबाव बढ़ने लगा। यह दबाव न केवल उनके अधीनस्थ उपनिवेशों की जनता एवं राष्ट्रीय नागरिकों की ओर से अपितु दो नई महाशक्तियों अमेरिका एवं सोवियत संघ की ओर से भी पड़ रहा था। 1945 के बाद अधिकांश पश्चिम अफ्रीका (अमेरिका का एशियाई उपनिवेश) और कुछ अन्य देशों ने बिना अधिक खून-खराबे के स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। केवल अल्जीरिया, हिंदचीन, मलाया, अंगोला, मोजांबिक और अन्य देशों को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए वर्षों के सशस्त्र संघर्ष के बाद आजादी प्राप्त हो सकी।

राजनीतिक स्वतंत्रता तुरंत वैसे लाभ लेकर नहीं आई, जिनका उपनिवेशों की जनता ने सपना देखा था। नए राष्ट्रों को आर्थिक विकास तथा आधुनिकीकरण संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिनका हल ढूंढना उनके लिए 'नव-उपनिवेशीकरण' से बचने की दृष्टि से जरूरी था। अधिकतर स्वतंत्र राष्ट्रों में जीवन का स्तर वैसा नहीं था जैसा कि पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका के 'विकसित' देशों में था और आज अनेक व्यक्तियों का भी यह मत है कि औपचारिक रूप से स्वतंत्र हुए देशों की दुनिया में आज भी औपनिवेशिक शासन के रूप या शोषण के पुराने प्रतिमान विद्यमान हैं।



उद्देश्य

इस पाठ का अध्ययन करने के पश्चात आप:

- कुछ राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलनों के बारे में जान पाएंगे;



आपकी टिप्पणियाँ

- वि-उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली वैश्विक राजनीतिक ताकतों का विश्लेषण कर पाएंगे;
- उत्तर-उपनिवेशवादी दुनिया में पर-निर्भरता और असमानता के संबंध की चर्चा कर पाएंगे और
- राष्ट्रीय विकास संबंधी कुछ समस्याओं और उनके कुछ प्रस्तावित समाधानों के बारे में जान पाएंगे।

26.1 राष्ट्रीय स्वाधीनता और राष्ट्रीय विकास के मॉडल-वि-उपनिवेशीकरण का प्रारंभ

मॉडल

बीसवीं सदी के राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलनों के नेताओं ने नागरिकता के इस आधुनिक विचार को प्रस्तुत करनेवाले राष्ट्रीय स्वाधीनता एवं विकास के पिछले उदाहरणों से प्रेरणा प्राप्त की कि एक राष्ट्र के सभी सदस्यों के समान अधिकार एवं दायित्व होने चाहिए।

अमेरिका के स्वाधीनता-संग्राम के बाद नए संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थायी प्रजातांत्रिक शासन की नींव पड़ी और धीरे-धीरे अमेरिका राष्ट्र के सभी सदस्यों को पूर्ण नागरिकता के अधिकार दे दिए गए। साथ ही अमेरिका की सेना का आकार छोटा रहा और उसने अक्सर नागरिक संस्थाओं के काम-काज में दखल नहीं दिया। एशिया तथा अफ्रीका के उपनिवेशों की जनता के लिए यह बहुत आकर्षक था जिन्हें नियंत्रण में रखने के लिए सेना का नियमित रूप से इस्तेमाल किया जाता था।

सन् 1789 की फ्रांस की क्रांति किसी विदेशी ताकत के खिलाफ शुरू नहीं हुई थी, अपितु क्रांतिकारियों ने यूरोप के अन्य भागों में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के सार्वभौमिक सिद्धांत फैलाने के लिए अभियान किया था। फ्रांस की क्रांति ने यूरोप के लोगों और फ्रांस के उपनिवेशों की जनता को इन सिद्धांतों के नाम पर फ्रांसीसी शासन के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया। इन राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों में से सभी प्रजातंत्र अथवा समानता में गहराई से विश्वास नहीं करते थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर यह मानते थे कि विदेशी शासन के खिलाफ लड़ने के लिए 'जनता' को तैयार करना होगा।

कुछ अन्य कारणों से भी औपनिवेशिक शासन के अधीन जी रहे लोगों ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता एवं विकास के 'अमेरिकी' मॉडल को सराहा। वर्ष 1865 से 1950 के बीच अमेरिकियों ने पूंजीवादी कृषि, भारी उद्योग और सामूहिक उपभोक्ता-व्यय पर आधारित विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था विकसित की। संसार भर में अनेक लोगों का यह मानना था कि संयुक्त राज्य अमेरिका वैश्विक पैमाने पर स्व-शासन के प्रति ईमानदारी से समर्पित है और वह संभवतः उपनिवेशों की जनता को उनके राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्रामों में प्रत्यक्ष रूप से सहायता प्रदान कर उपनिवेशवाद के खिलाफ एक ताकत की तरह कार्य करेगा।

1917-1921 की रुसी (बोल्शेविक) क्रांति का विश्व पर भारी वैश्विक प्रभाव पड़ा। बोल्शेविकों का तर्क था कि समूचे विश्व में विभिन्न 'राष्ट्रीयताओं' को स्वतंत्र रहने एवं अपना भविष्य तय करने का अधिकार है। रुसी क्रांति ने भी पूंजीवादी पश्चिमी देशों से भिन्न तीव्र सामाजिक तथा आर्थिक 'विकास' का एक दैकल्पिक प्रतिमान प्रस्तुत किया।



आपकी टिप्पणियाँ

1941 में अनेक रूसी नागरिकों का भौतिक जीवन-स्तर अपने दादा-दादियों की तुलना में उच्चतर था।

रूसी नेताओं ने राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से शासित अनेक देशों एवं उपनिवेशों के नागरिकों को 'नैतिक' एवं भौतिक सहायता प्रदान की। मार्क्सवादी सिद्धांत ने सिखाया कि संसार भर के छोटे किसानों और प्रोलेतेरियनों के हित समान हैं और बुर्जुआओं तथा साम्राज्यवादियों को हटाने के लिए उन्हें सहयोग की आवश्यकता है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का आयोजन सीखने के लिए कुछ उपनिवेशों के राष्ट्रवादियों ने सोवियत संघ का दौरा किया था, वहां जाकर अध्ययन किया। इनमें वियतनामी राष्ट्रवादी हो ची मिन्ह, चीनी राष्ट्रवादी चियांग काईशेक (1887-1975) और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता जवाहर लाल नेहरू शामिल थे, जो प्रजातांत्रिक समाजवाद में यकीन रखते थे और जिनका विचार था कि सोवियत प्रभुत्व वाली अर्थव्यवस्था का अनुकरण कर सकता है।

वि-उपनिवेशीकरण की शुरुआत

ग्रेट ब्रिटेन एवं फ्रांस स्व-शासन और 'स्व-राज्य' के लिए बढ़ते प्रदर्शनों में से कुछ पर ध्यान देने के लिए बाध्य हुए। 1867 में ही ब्रिटेन ने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका को तथा कनाडा के कुछ भागों को, जहां के मूल निवासियों को भगाकर या मारकर 1600 ई.से बड़ी संख्या में यूरोप के लोग बस गए थे, कारगर स्व-राज्य प्रदान करना शुरू कर दिया। इन स्थानों के गोरे उपनिवेशियों को निर्वाचित विधानसभाओं और विधायिका एवं संसदों के माध्यम से 'घरेलू' मामलों में निर्णय लेने की स्वतंत्रता दे दी गई, किंतु अन्य उपनिवेशों तथा राष्ट्रों के साथ उनके संबंधों पर लंदन की राजशाही का ही नियंत्रण रहा। 1910 के बाद इन उपनिवेशी राष्ट्रों को स्वतंत्र उपनिवेश अथवा सहयोगी राष्ट्रों का ब्रिटिश राष्ट्रमंडल कहा जाने लगा। ब्रिटेन ने दक्षिण अफ्रीकी संघ को भी राष्ट्रमंडल का दर्जा प्रदान कर दिया (जहां काले अफ्रीकियों ने संख्या में यूरोपियों को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन उन्हें मतदान की अनुमति नहीं थी)।

ब्रिटिश और अन्य पश्चिमी देशों की भांति, अनेक फ्रांसीसियों का मानना था कि कुछ 'जातियाँ' एवं समाज, खासकर उनकी जाति और समाज उन्नत हैं, जबकि अन्य जातियाँ और समाज 'आदिम' हैं। उनका कहना था कि उन्नत समाजों का यह नैतिक दायित्व है कि वे ज्यादा पिछड़े समाजों का मार्गदर्शन करें या उन्हें शिक्षित करें। 1914 के बाद फ्रांसीसी उपनिवेशों में गैर-फ्रांसीसी लोगों को अपने समाज के शासन में मतदान द्वारा सहभागिता करने अथवा विधानसभाओं में सेवा करने की इजाजत दे दी गई।

ब्रिटिश, फ्रांसीसी और डच औपनिवेशिक शासन इस बात को मानने लगे थे कि उपनिवेशों के लोग भावनात्मक कारणों (जैसे यूरोपीय संस्कृति के प्रति सराहना) से अथवा इस कारण से कि वे अपने मातृ-देश से जुड़े रहने से आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे, इस आंशिक स्वतंत्रता को स्वीकार कर लेंगे। अनेक उपनिवेशों ने पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की ओर पहले कदम के रूप में यूरोपीय मार्गदर्शन के अंतर्गत ढीले-ढाले राज्य-संघ की योजना को स्वीकार कर लिया। किंतु कुछ उपनिवेशों में जैसे कि भारत में, राष्ट्रवादी पूर्ण स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते रहे।



हमें यह भी जानना चाहिए कि 1945 के पहले औपनिवेशिक शासन में किए गए संशोधनों ने वास्तव में यूरोपीय उपनिवेशवादियों की स्थिति को कमजोर नहीं बनाया और उपनिवेशों के थोड़े से 'मूल निवासियों' को ही लाभ पहुंचाया।

26.2 उपनिवेशवाद-विरोधी संघर्ष पर द्वितीय विश्व-युद्ध का प्रभाव

द्वितीय विश्व-युद्ध ने औपनिवेशिक दुनिया के उन लोगों को भी प्रेरित कर दिया जो पहले राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलनों से अछूते रह गए थे। कुछ मामलों में उपनिवेश के लोगों द्वारा नए आक्रांताओं (मुख्यतः जापान) के विरुद्ध किए जा रहे सैन्य संघर्षों को उपनिवेशों पर पुनः कब्जा करने की कोशिश करने वाले यूरोपियों के विरुद्ध संघर्षों में बदल दिया। अफ्रीकियों एवं एशियाइयों को विश्व के सुदूर कोनों में जर्मनी, इटैलियों और जापानियों के विरुद्ध लड़ने के लिए औपनिवेशिक सेनाओं में शामिल कर लिया गया। जहाँ उन्होंने यह सीखा कि यूरोपियन पृथ्वी के अजेय अधिपति नहीं हैं। युद्ध के दौरान लगभग पचास लाख भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश नेतृत्व वाली सेनाओं में सेवा की। एशियाई और अफ्रीकी सैनिकों का दूसरे उपनिवेशों के लोगों और यूरोपीय तथा अमेरिकी सैनिकों व नागरिकों के साथ संबंध था। जर्मन एवं जापानी आतंक 'तानाशाही' से लड़ने के लिए प्रशिक्षित इन सैनिकों ने अपने स्वयं के औपनिवेशिक शासकों के लिए खतरा उत्पन्न कर दिया। 1940 के दशक में एशिया, अफ्रीका और कैरेबियाई देशों में पुलिस और सैनिकों (अपने 'देशवासियों' सहित) के हमलों के बावजूद उपनिवेशी जनता सामूहिक प्रदर्शनों में शामिल हुई। 1945 तक युद्ध से पहले की तुलना में और अधिक जनता ने पूर्ण नागरिकता के अधिकार एवं राष्ट्रीय स्वाधीनता की माँग करनी शुरू कर दी और वे अपनी मांगों का विरोध करने वालों से लड़ने के लिए ज्यादा आत्मविश्वास से भरे थे।

1939 से पहले अफ्रीकी बुद्धिजीवी, पेशेवर और सिविल सेवकों ने राष्ट्रवादी आंदोलनों का आधार तैयार कर दिया था। फिर भी 1945 के बाद इन लोगों को अपने ही देश से अधिक दबाव एवं श्रमिक वर्ग की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने तथा अपने राष्ट्रीय स्वतंत्रता अभियानों में नेताओं को किसानों और श्रमिक स्त्री-पुरुषों की ओर से प्रजातांत्रिक सुधारों और आर्थिक समानता के लिए ज्यादा सशक्त मांगें शामिल करने का दबाव झेलना पड़ा।

राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम

1930 के दौरान फ्रांसीसी हिंदचीन में हो ची मिन्ह ने साम्यवादी विचार फैलाने की कोशिश की। 1940-41 में जापानियों ने फ्रांस को हिंदचीन से बाहर खदेड़ दिया और उस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। उन्हें भगाने के लिए हो ने एक राष्ट्रीय जन मोर्चा (वियत मिन्ह) बनाया और जब 1945 में फ्रांसीसी, ब्रिटेन और अमेरिका की सहमति से पुनः हिंदचीन के शासक बन गए तब हो और वियत मिन्ह ने फ्रांस के खिलाफ लड़ना जारी रखा तथा 1954 तक अधिकांश हिंदचीन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। इसी वर्ष वियतनाम नाममात्र के स्वतंत्र देशों में विभक्त हो गया, जिनमें से उत्तरी क्षेत्र हो और उसके सहयोगियों के नियंत्रण में आ गया और दक्षिणी भाग पर अमेरिका की राजनीति, सैन्य एवं आर्थिक उपस्थिति बढ़ने लगी। इस टकराव में लगभग 50,000 अमेरिकी सैनिक मारे गए और लाखों वियतनामियों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा, लेकिन वियतनामियों ने 1975 में विश्व की सबसे बड़ी साम्राज्यवादी शक्ति को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया।



आपकी टिप्पणियाँ

भारत में पूरे देश में कांग्रेस के नेतृत्व में ब्रिटिश शासन के खिलाफ सामूहिक आंदोलन हुए। इसके अलावा साम्यवादियों के नेतृत्व में मजदूरों और किसानों द्वारा और साथ ही युवाओं, लेखकों, महिलाओं एवं निम्न जातियों के संगठनों द्वारा स्वतंत्र आंदोलन भी चलाए जा रहे थे। 1947 में ब्रिटिशों को भारत छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। स्वतंत्रता विभाजन बंटवारे और दो स्वतंत्र राष्ट्रों भारत एवं पाकिस्तान के निर्माण के साथ प्राप्त हुई।



पाठगत प्रश्न 26.1

1. 1867 से 1914 के बीच स्वतंत्र अथवा अर्द्ध-स्वतंत्र हुए कुछ देशों के नाम बताइए।
2. द्वितीय विश्व युद्ध ने उपनिवेशीकृत देशों के लोगों को किस प्रकार प्रेरित किया?
3. 1945 के बाद सशस्त्र संघर्ष से राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले कुछ देशों के नाम बताइए।

26.3 औपनिवेशिक राष्ट्रवाद, स्वाधीनता संग्राम और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

सन् 1945 के बाद एशिया और अफ्रीका के कुछ औपनिवेशिक राष्ट्रवादी नेताओं ने सोवियत अथवा अमेरिकी सहायता मांगी अथवा पाई और उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ (1945 से जिसका मुख्यालय अमेरिका में है) जैसे नए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से निष्कपट वार्ता की उम्मीद हुई। उन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता और विकास के समान हितों वाले स्वतंत्र राष्ट्रों का एक क्षेत्रीय संघ भी बनाया। इन संघों में से एक अफ्रीकी एकता संगठन (ओ.ए.यू.) था, जिसकी स्थापना 1963 में नए राष्ट्रों के बीच होने वाले विवादों में मध्यस्थता करने तथा औपनिवेशिक ताकतों को अपने शेष अधीनस्थ राष्ट्रों से चले जाने के लिए बाध्य करने हेतु हुई थी। एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम था गुटनिरपेक्ष आंदोलन (एन.ए.एम.) का अस्तित्व में आना, जिसमें अन्य देशों के अलावा चीन, भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, ईरान और मिश्र शामिल थे। 1955 में साम्राज्यवाद, राष्ट्रीय आक्रमण, जातिवाद और अधिक हथियारों की निंदा करने के लिए बांडुंग, इंडोनेशिया में 29 राष्ट्रों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया।

गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने तीसरी दुनिया के देशों द्वारा आपस में तथा दोनों महाशक्तियों के साथ शांतिपूर्ण सहयोग की आवश्यकता बताई। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देशों में से अधिकतर के नेता एक मध्यम मार्ग खोजने और अपनाना चाहते थे, जो न तो विशुद्ध साम्यवादी हो और न ही विशुद्ध पूंजीवादी। 1950 के दशक से 1970 के दशक के बीच समाजवाद एवं प्रजातंत्र के एशियाई और अफ्रीकी 'मार्गों' पर खूब चर्चा हुई। अफ्रीका के अनेक नए राष्ट्र स्वतंत्र होते ही तानाशाही के अधीन हो गए, जैसे जायरी (पूर्व बेल्जियम उपनिवेश) जो मोबुतो सेस सेको (राष्ट्रपति, 1965-1977) के अधीन और युगांडा (पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश) इदी अमीन दादा (1924-2003, 1979 में पदच्युत) के अधीन था।



आपकी टिप्पणियाँ

सहारा अफ्रीका (जैसे मिस्र एवं लीबिया) के कुछ नेताओं ने आर्थिक विकास के मामलों में और इजराइल राष्ट्र (पूर्व ब्रिटिश फिलस्तीन) को फिलस्तीनी भूमि का अवैध, अर्द्ध-औपनिवेशिक कब्जा समाप्त करवाने में मध्यपूर्वी राष्ट्रों के साथ सहयोग किया। यह अखिल अरब आंदोलन का एक हिस्सा था। 1970 के दशक से 1980 के दशक के बीच 'काले अफ्रीका' के नेता रोडेशिया और दक्षिण अफ्रीका गोरे-अल्पसंख्यक शासनों पर जाति भेद और काले लोगों के साथ पक्षपात खत्म करने के लिए दबाव डालते रहे। उन्होंने गोरी-अल्पसंख्यक सरकारों द्वारा गैर-कानूनी करार दिए गए (जैसे दक्षिण अफ्रीका की अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस) को मदद पहुंचाई।

नव-स्वतंत्र राष्ट्रों को शीतयुद्ध के दौर (1945-1991) में राष्ट्रीय स्वाधीनता और विकास संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। साम्यवाद के प्रति सहानुभूति रखने वाले-या कम से कम उसका विरोध न करने वाले नेताओं को अक्सर लोकप्रियता मिलने लगी। लेकिन जब उन्होंने पुराने औपनिवेशिक 'मूल' श्रेष्ठजनों की स्थिति कमजोर करने की कोशिश की तो उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा।

इंडोनेशिया में स्वतंत्रता सेनानी अहमद सुकर्णो (1901-1970) ने 1920 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे इंडोनेशिया ने राष्ट्रीय स्वाधीनता के पांच सिद्धांत प्रतिपादित किए : ईश्वर में आस्था, मानवतावाद, राष्ट्रीय स्वाधीनता, प्रजातंत्र और सामाजिक न्याय (जिसका अर्थ था केंद्रीय आर्थिक मार्गदर्शन एवं धन का पुनः वितरण)। मुसलमान (बहुसंख्यक धार्मिक समुदाय) इस शर्त पर केंद्रीकृत इंडोनेशियाई राष्ट्र द्वारा शासन के लिए सहमत हुए कि उन्हें उनके पास कुछ स्थानीय नियंत्रण, विशेषकर धार्मिक मामलों में रहेगा। 1950 के दशक में सुकर्णो ने चीनियों से प्रेरित साम्यवादी जन-आंदोलन भी शुरु किया, किंतु 1959 में उन्होंने तानाशाही स्थापित कर दी हालांकि उन्होंने साम्यवादी आंदोलन की वैधता स्वीकार की। 1965 में सुकर्णो के आंतरिक दुश्मनों (मुख्यतः सैन्य अधिकारियों) ने उन्हें अपदस्थ कर दिया और हजारों लोगों का कत्ल करते हुए इंडोनेशियाई साम्यवादियों पर शिकंजा कसना प्रारंभ कर दिया। सोवियत संघ किनारे खड़ा यह सब देखता रहा, जबकि अमेरिका ने सैन्य अधिकारियों को गुप्त रूप से मदद की। इंडोनेशिया में अभी हाल तक सैन्य तानाशाही बनी हुई थी।



पाठगत प्रश्न 26.2

बाएं कॉलम में दिए गए शब्दों को दाएं कॉलम में दिए गए अर्थ से या शब्द को मिलाइए।

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. इदी अमीन | 1945 में स्थापित |
| 2. सुकर्णो | इसमें भारत शामिल है। |
| 3. गुटनिरपेक्ष आंदोलन | अफ्रीकी तानाशाह |
| 4. संयुक्त राष्ट्र संघ | इंडोनेशिया |



आपकी टिप्पणियाँ

26.4 वि-उपनिवेशीकरण और वैश्विक राजनीति

उपनिवेशवाद का विरोध करने पर हजारों स्त्री-पुरुषों को कष्ट झेलने पड़े, जैसे—फ्रांसीसी द्यूनीशिया (उत्तरी अफ्रीका) में स्वतंत्रता-आंदोलन के नेता हबीब बुर्गीबा (1903-2000) में और ब्रिटिश पश्चिमी अफ्रीका में घाना के स्वाधीनता-संग्राम की प्रमुख हस्ती क्वामे एनक्रूमाह (1909-1972) को तथापि अन्य नेता अपने औपनिवेशिक शासकों के गृह-राष्ट्रों में रहकर युद्ध के समय राजनीतिक विचार तथा संगठन की तकनीकें सीखते रहे। हो चि मिन्ह (1894-1969) 1918 से 1930 के बीच फ्रांस में रहे, जहाँ उन्होंने वियतनामी स्वतंत्रता हेतु लड़ने के लिए फ्रांसीसी हिंदचीन लौटने से पहले फ्रांसीसी साम्यवादी दल की स्थापना की। लियोपोल्ड सेवर सेनघोर (1906-2001) फ्रांस में एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर और कवि थे और सेनेगल के प्रजातांत्रिक ब्लॉक का नेतृत्व करने के लिए अपने मूल स्थान पश्चिम अफ्रीका लौटने से पहले वे 1960 से 1980 तक सेनेगल के प्रथम राष्ट्रपति रहे।

1945 के बाद वि-उपनिवेशीकरण में तेजी आई। कुछ क्षेत्रों में सीमित हिंसा एवं जन-हानि के साथ वि-उपनिवेशीकरण हो गया। उदाहरण के लिए, 1958 के बाद फ्रांसीसी आधिपत्य वाला पश्चिमी अफ्रीका स्वतंत्र सेनेगल, मारीशियाना, माली, आइवरी कोस्ट, गीनिया और अन्य राष्ट्रों में विभाजित हो गया, जबकि ब्रिटिश आधिपत्य वाला पश्चिमी अफ्रीका 1957 से 1961 के बीच सियरा तिओन और नाइजीरिया के स्वतंत्र राष्ट्रों में बंट गया।

सन् 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने हजारों भारतीयों को जेलों में ठूस दिया। लेकिन उसके बाद भारतीय स्वाधीनता संग्राम में भारतीयों और अंग्रेजों के बीच कम हिंसा हुई। फिर भी लाखों दक्षिण एशियाई आगामी भारत-पाकिस्तान बंटवारे के समय अपनी जान से हाथ धो बैठे या सीमाओं के पार विस्थापित हो गए। पूर्व ब्रिटिश राज के कुछ पड़ोसी क्षेत्र जैसे सीलोन (अब श्रीलंका) और बर्मा (अब म्यांमार) कम हिंसा से ही स्वाधीन हो गए।

1950 के दशक में उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को एवं द्यूनीशिया शांतिपूर्वक फ्रांस के चंगुल से अलग हो गए, लेकिन पड़ोसी अल्जीरिया को आठ वर्षों के संघर्षों के बाद स्वतंत्रता प्राप्त हुई, जिसमें हजारों अल्जीरियाई और फ्रांसीसी मारे गए। आज के अंगोला एवं मोजांबिक (दक्षिण अफ्रीका में) ने एक दशक की लड़ाई के बाद 1975 में पुर्तगाली शासन से अपने को स्वतंत्र कराया, जिसमें बड़ी संख्या में अफ्रीकियों और पुर्तगालियों की जानें गईं। वर्तमान मलेशिया की जनता ने दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान जापानी कब्जे के खिलाफ संघर्ष किया। इसी मलायी जापान-विरोधी जन-सेना ने फिर ब्रिटेन द्वारा पुनः कब्जा किए जाने के खिलाफ लड़ाई की। अगले 10 वर्षों में एक समय 100,000 से अधिक ब्रिटिश सैनिक ब्रिटिश नेताओं द्वारा कथित 'साम्यवादी बगावत' कुचलने के लिए मलाया में उपस्थित थे। 1957 में ब्रिटेन को अपनी सेनाएं वापस बुलानी पड़ीं और ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के एक अर्ध-स्वतंत्र सदस्य के रूप में मलेशियाई संघ को मान्यता देनी पड़ी।

1945 के बाद अर्थात् दोनों महाशक्तियों के गुटों के बीच शत्रुता से वि-उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया का शीतयुद्ध गहरा रिश्ता रहा है। जिनमें से 'पहली दुनिया' की अगुआई अमेरिका कर रहा था, जो पूँजीवादी प्रजातंत्र का पक्षधर माना जाता था, और दूसरी



आपकी टिप्पणियाँ

दुनिया की प्रणाली की प्रतिनिधित्व सोवियत संघ तथा चीन गणराज्य जैसे उभरते समाजवादी राष्ट्र कर रहे थे। उपनिवेश की बेड़ियों से मुक्त हुई तीसरी दुनिया के नए राष्ट्रों को दोनों महाशक्तियों में से किसी एक के साथ निकट संबंध बना लेने से लाभ हुआ।

1945 में कोरिया से जापान के निकलने के बाद कोरिया जलडमरू का उत्तरी भाग सोवियत संघ एवं चीन गणराज्य के प्रभाव में आ गया, जबकि दक्षिणी भाग अमेरिका पर आश्रित हो गया। 1953 से 1970 के बीच अमेरिका ने दक्षिण कोरिया को 'विकास सहायता' के तौर पर दस बिलियन डॉलर से अधिक की राशि दी। अर्थशास्त्री 1970 के दशक से ही दक्षिण कोरिया, ताइवान, हांगकांग और सिंगापुर को निर्यात के लिए एशिया को 'नन्हे ड्रैगन' कहने लगे थे। 'बड़े ड्रैगन' औद्योगिक वस्तुओं (जैसे इस्पात, जहाज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण) के उत्पादन पर आधारित अपनी तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं के कारण जापान एवं चीनी गणराज्य कहलाते थे। नन्हे ड्रैगन विकसित देशों, मुख्यतः अमेरिका, जापान और ग्रेट ब्रिटेन से मिलने वाली भारी सहायता राशि और ऋणों के साथ-साथ व्यापारिक समझौतों से लाभान्वित हुए।

किंतु अफ्रीका में यूरोपीय देशों ने अपने आधिपत्य वाले अफ्रीकी देशों में शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य मानव-विकास संबंधी जरूरतों पर थोड़ा ही धन लगाया। यहां तक कि लैटिन अमेरिका में जहाँ 1900 तक कुछ औपचारिक उपनिवेश बने हुए थे, अनेक लोग लगभग गरीब, अशिक्षित और राजनीतिक रूप से शक्तिहीन बने रहे, जैसे 18वीं एवं 19वीं सदी में उनके पूर्वज थे।



पाठगत प्रश्न 26.3

1. 1945 के बाद की महाशक्तियों ने किस प्रकार उपनिवेश-विरोधी संघर्ष में अपनी रुचि प्रदर्शित की?
2. 1953 से 1980 के बीच एशिया के कुछ 'नन्हे ड्रैगनों' के नाम बताइए?
3. 1945 के बाद कौन-से महाद्वीप अधिकसित बने रहे?

26.5 चीन : राष्ट्रीय स्वाधीनता, दो राष्ट्र

1911-1912 में एक सम्राट द्वारा नियंत्रित चीनी तानाशाही प्रणाली औपचारिक रूप से समाप्त हो गई और उसके स्थान पर गणराज्य बन गया, लेकिन नया गणराज्य विदेशी आधिपत्य को हटाने में असमर्थ रहा। 1920 के दशक के अंतिम घरण में माओ जेडोंग, (1893-1976) चाऊ एनलाई, डेंग झिआओपिंग एवं अन्य नेताओं के नेतृत्व में साम्यवादियों ने चीनी राष्ट्रवादियों (गुओमिनडंग) के विरुद्ध लड़ाई लड़ी और दोनों ही समूहों ने जापान को खदेड़ने की कोशिश की जिसने 1840 के दशक से उन पर क्षेत्रीय



आपकी टिप्पणियाँ

और आर्थिक नियंत्रण बनाया हुआ था। माओ का मानना था कि चीनी राष्ट्रवादी ऐसे सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन नहीं लाना चाहते, जिनसे चीन की जनता का उद्धार हो सके और वे इतने अधिक भ्रष्ट हैं कि विदेशियों का विरोध नहीं कर सकते। इसलिए चीन के साम्यवादी नेताओं ने 1949 तक न केवल जापानी, फ्रांस और ब्रिटेन को अधिकांश 'राष्ट्रीय' क्षेत्र से बाहर निकालने के लिए बाध्य किया, वरन् अपने विरोधी चीनी 'राष्ट्रवादियों' गुओमिनडंग को मुख्यभूमि चीन से एक-एक पतली खाड़ी के पार फॉर्मोसा द्वीप-वर्तमान ताइवान में धकेल दिया। हांगकांग 1977 तक ब्रिटेन का उपनिवेश था। उनका परम उद्देश्य ताइवान को चीनी मुख्य भूमि के साथ एकीकृत करना था, जो एक अलग राष्ट्र बन गया था।

1945 से चीन में इतिहास की संभवतः सबसे बड़ी क्रांति आई, जिसमें उसने खुद को मूल श्रेष्ठजनों और ब्रिटेन, फ्रांस तथा अमेरिका के भी, जिनका देश के अधिकांश व्यापार पर नियंत्रण था, प्रभुत्व वाले किसान-बहुल समाज से चीनी लोकतांत्रिक गणराज्य नामक एक समाजवादी राष्ट्र में बदल डाला। समाजवादी राष्ट्र का मतलब था राष्ट्र के स्वामित्व वाले औद्योगिक उद्यम और सामूहिक स्वामित्व वाली भूमि पर सामूहिक खेती की नीति।

किंतु 1980 से चीनी साम्यवादी दल (सीपीसी) के नेतृत्व ने विनिर्माण और वाणिज्यिक क्रियाकलापों में मुक्त उद्यम को बढ़ावा दिया है। 1993 तक चीनी गणराज्य का दस प्रतिशत से भी कम औद्योगिक उत्पादन केंद्रीय योजना के अधीन था। 1980 के दशक से चीनी गणराज्य ने अपने वैचारिक विरोधी देशों से सैकड़ों बिलियन (अमेरिकी) डॉलर के विदेशी निवेश का स्वागत किया है। कुछ अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि चीनी गणराज्य 2010 तक विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा, जैसा कि वह 1800 से पूर्व था, लेकिन आर्थिक उदारीकरण एवं सरकारी नियंत्रण में कुछ ढिलाई बरतने से 1949-1980 के रुझान को उलट भी दिया, जब सीपीसी का लक्ष्य चीनियों को हर संभव तरीके से अधिकाधिक समान बनाना था।

एक ओर जहां चीनी गणराज्य ने पश्चिमी आक्रमण तथा परमाणु हथियारों के विकास की निंदा की वहीं दूसरी ओर वह 1960 के दशक के प्रारंभ तक परमाणु हथियार-संपन्न राष्ट्र बन गया। चीनी नेताओं ने अपने सैन्य निर्माण को यह कहकर उचित ठहराया कि कोरियाई युद्ध (1950-1953) के दौरान अमेरिका ने चीनी गणराज्य पर परमाणु बम गिराना चाहा था। साथ ही 1950 के दशक में चीन और रूस के रिश्ते बिगड़ने लगे थे, क्योंकि माओ का मानना था कि मार्क्सवाद एवं लेनिनवाद को चीन की स्थितियों के अनुसार समायोजित किए जाने की आवश्यकता है और उन्हें तथा कुछ अन्य नेताओं को सोवियत प्रभुत्व की आशंका थी। 1960 एवं 70 के दशक के दौरान सोवियत संघ ने वियतनामी साम्यवादियों को अमेरिका के विरुद्ध संघर्ष में सैन्य सहायता मुहैया करवाई थी, लेकिन चीन ने वियतनामी के साम्यवादी आंदोलन का समर्थन करने से मना कर दिया। इस समय चीन अफ्रीका में चल रहे साम्यवाद-समर्थक जन-संग्राम को मदद कर रहा था। चीन ने तीसरी दुनिया के अनेक देशों को विकास संबंधी सहायता उपलब्ध कराई।



पाठगत प्रश्न 26.4

1. सीपीसी द्वारा 1930 से चीन के दुश्मनों के रूप में चिह्नित दो राष्ट्रों के नाम बताइए।



आपकी टिप्पणियाँ

2. क्या प्रमाण हैं कि चीन के साम्यवादी नेतृत्व ने 1980 से समाजवाद और विकास की अपनी संकल्पना में संशोधन कर लिया?

3. क्या चीनी गणराज्य ने वियतनाम के स्वाधीनता संग्राम को मदद पहुंचाई या हतोत्साहित किया?

26.6 उपनिवेशोत्तर विश्व में 'विकास' की समस्याएँ

द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान और बाद में बड़ी शक्तियों के नेतृत्व ने वैश्विक स्तर पर अधिक समान धन-वितरण को विश्व-शांति और स्थायित्व के लिए अनिवार्य माना। 1945 के बाद धन उत्पादन और व्यापार में पैठ को लेकर होने वाले विवादों के समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसी नई वैश्विक संस्थाओं की स्थापना की गई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष उन देशों के लिए ऋणों की व्यवस्था करता है जो उन्हें आयातों पर होने वाले अपने व्यय को 'संतुलित' करने के लिए अपने निर्यातों से पर्याप्त धन नहीं जुटा पाते। विश्व बैंक सिंचाई और जल-विद्युत प्रणालियों के लिए भुगतान करने और उत्पादकता तथा आर्थिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए अपेक्षित अन्य बुनियादी सुविधा विषयक सुधार करने के लिए राष्ट्रों को ऋण देता है, जो प्रायः 'विकास सहायता' के पूरक के रूप में दिए जाते हैं।

किंतु अनेक लोगों का कहना है कि इन संस्थाओं ने उन्हीं राष्ट्रों के हित पूरे किए हैं, जो पहले से ही विकसित हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष लेने वाली सरकारों से अपना घाटा कम करने की अपेक्षा करता है, जिसे ये सरकारें अक्सर 'सामाजिक मदों पर व्यय' (जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास के लिए निधि प्रदान करना) घटाकर करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने सरकारों को अपनी मुद्राओं का अवमूल्यन करने का परामर्श भी दिया है जिससे विश्व बाजार में उनके द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की कीमत कम हो जाती है।

संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थायी सुरक्षा परिषद में 1945 के बाद रूस, अमेरिका, राष्ट्रवादी चीन (1970 तक), ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस शामिल थे। शीतयुद्ध के दौरान ब्रिटेन और फ्रांस ने सुरक्षा परिषद में उठाए गए लगभग दो-तिहाई मुद्दों पर अमेरिका का पक्ष लिया, जिससे विश्व की राजनीति तथा आर्थिक मसलों पर अमेरिकी प्राथमिकताएं और निर्णय हावी रहे। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कुछ व्यक्तियों की दृष्टि में विकसित पूंजीवादी समाजों के नेताओं द्वारा स्वाधीनता एवं न्याय के संबंध में किए गए दावे अक्सर खोखले लगते हैं और उनके द्वारा बनाई गई नीतियां पाखंड प्रतीत होती हैं। दूसरी ओर विश्व भर में लोग पत्रिकाओं, सिनेमा और टेलीविजन के माध्यम से 'पश्चिमी' जीवनशैली के गहन संपर्क में आए, जिससे वे पश्चिमी (विशेषकर अमेरिकी) तरीकों से अपने आर्थिक तथा अन्य क्रियाकलाप व्यवस्थित करने लगे। अमेरिकी अर्थशास्त्री डब्ल्यू डब्ल्यू रोस्टो मानते थे कि पूर्ववर्ती उपनिवेश ब्रिटेन जैसे प्रारंभिक औद्योगिक राष्ट्रों द्वारा अपनाए गए मार्ग पर चल सकते हैं और वे अपने कृषि-उत्पादन बढ़ाकर तथा मुक्त व्यापार की नीतियों का अनुसरण करके उद्योग विकसित करने के लिए पूंजी एकत्र कर सकते हैं और इस



आपकी टिप्पणियाँ

प्रकार आर्थिक आधुनिकता की दिशा में बढ़ सकते हैं। विकास के इस सिद्धांत को 'आधुनिकीकरण का सिद्धांत' कहते हैं।

पहले अर्जेंटीना और फिर ब्राजील ने इस मॉडल को अपनाने का प्रयास किया और कुछ उद्योग भी लगाए, लेकिन अनेक अमेरिकी, अफ्रीकी और एशियाई देशों में 1960 के दशक से 1980 के दशक के बीच विकास के संकट के संकेत दिखे। औद्योगिकीकरण ठहर गया और गरीबी बढ़ गई। 1960 के बाद लैटिन अमेरिका में विदेशी कंपनियों निवेशित धन से कहीं अधिक धन (लाभ के रूप में) निकालकर ले गईं। निजी निकायों जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लिए गए ऋणों से हालात नहीं सुधरे। 1980 के दशक में लैटिन अमेरिकी देशों को कुल 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक ऋण अदायगी करनी थी। 1990 के दशक के प्रारंभ में 60 प्रतिशत से अधिक लैटिन अमेरिकी परिवार अपनी मूलभूत आवश्यकताएं, जैसे—भोजन, कपड़ा और मकान पूरी करने लायक भी नहीं कमा पाते थे। अफ्रीका में आर्थिक स्थिति और खराब थी, 1980 के दशक में जाइरा एवं बुरुंडी जैसे अफ्रीका के कुछ देशों में नकारात्मक संवृद्धि होने लगी।

लैटिन अमेरिका के अर्थशास्त्रियों एवं वैज्ञानिकों ने रोस्टो जैसे अर्थशास्त्रियों द्वारा दिए गए तर्कों और कुछ पश्चिमी नेताओं द्वारा प्रवर्तित विकास संबंधी सिद्धांत की आलोचना की। यह आलोचना कभी-कभी 'निर्भरता नीति' अथवा 'अल्पविकास का सिद्धांत' कही जाती है। राउल प्रेविस्च और अन्य 'निर्भरता सिद्धांतवादियों' ने दावा किया कि शताब्दियों के स्पेनी एवं पुर्तगाली शासन और उसके बाद ब्रिटेन, अमेरिका तथा अन्य देशों द्वारा दशकों के आर्थिक प्रभुत्व के कारण अधिकतर लैटिन अमेरिकी देशों को अपनी स्वतंत्रता कार्यान्वित करने में, खासकर रोजगार और आर्थिक संसाधनों के उपयोग जैसी मौलिक परिस्थितियों के संबंध में, असमर्थ बना दिया। प्रेविस्च की भांति 1970 के दशक में अफ्रीका में वाल्टर रॉडनी ने पाया कि उपनिवेश सदियों के उपनिवेशवाद के दौरान सृजित 'निर्भरता पैटर्न' से आसानी से बाहर नहीं निकल सकते। (यूनिट 5.1 में साम्राज्यवाद पर की गई चर्चा देखें)। उनका दावा था कि जब तक बड़े जमींदार गरीब किसानों एवं श्रमिकों का शोषण करना बंद नहीं करेंगे, तब तक कृषि पिछड़ी ही रहेगी : बड़ी जागीरों (जैसे भारत में जमींदारी) तोड़ कर किसानों को पुनः वितरित की जानी चाहिए। 'तीसरी दुनिया' के अनेक सफल राजनेताओं ने सोवियत संघ एवं चीन के अनुभवों के आधार पर उद्यमों और संसाधनों पर राष्ट्र के स्वामित्व अथवा नियंत्रण पर आधारित आर्थिक विकास की रणनीति अपनाई है। उन्होंने विदेशी निवेशकों एवं राष्ट्रों को भारी लाभ प्राप्त करने से रोकने और मुफ्त शिक्षा, सुलभ स्वास्थ्य सुविधाओं आदि के माध्यम से गरीबों का उत्थान करने की भी कोशिश की है। उदाहरण के लिए क्यूबा में फिदेल कास्त्रे (1927) ने 1950 के दशक के उत्तरार्ध में एक राष्ट्रवादी क्रांति का नेतृत्व किया और क्यूबाई जनता के हित के लिए हितकर नीतियों का अनुसरण करते रहे। कास्त्रों क्रांति कुछ लैटिन अमेरिकी देशों में लोकप्रिय रही है, जो अपने देश की अमेरिका द्वारा प्रेरित तानाशाही एवं सतत विदेशी प्रभाव से नाराज हैं। अधिकांश क्यूबा निवासी का जीवन-स्तर धनी देशों के लोगों की तुलना में बेहतर है।

1960 के बाद अन्य लैटिन अमेरिकी देशों ने कुछ संदर्भों में क्यूबा के उदाहरण को अपनाया। 1970 में सल्वाडोर अलेंडे एक समाजवादी के रूप में चिली के राष्ट्रपति चुने गए। अपने संक्षिप्त कार्यकाल में उन्होंने चिली के विदेशी निगमों द्वारा नियंत्रित खनिज



आपकी टिप्पणियाँ

संसाधनों के 'राष्ट्रीयकरण' का प्रयास किया। लेकिन वे अमेरिका की मदद से आंतरिक दु मनों द्वारा 1973 में अपदस्थ कर मार दिए गए और उनके स्थान पर एक तानाशाह (जनरल पिनोचे) आकर 1990 तक पदासीन रहे। हाल ही में एक सेनाधिकारी ह्यू चावेज (1954) 1998 में वेनेजुएला के राष्ट्रपति चुने गए। वेनेजुएला को गरीबी से उबारने के लिए राष्ट्र के स्वामित्व वाली तेल-कंपनियों से प्राप्त राजस्व का इस्तेमाल किया। उनके कार्यकाल के पहले वर्ष सामाजिक कार्यक्रमों पर सरकारी व्यय नाटकीय रूप से बढ़ा और वे काफी कारगर ढंग से अमेरिका का मुकाबला करने में सफल रहे। क्यूबा में कास्त्रे का शासन एवं वेनेजुएला में चखेज का उदय राष्ट्रवादी विकासशील विश्व के भागों में बल और विकास के जनोन्मुखी प्रतिमान को प्रदर्शित करते हैं।



पाठगत प्रश्न 26.5

बाईं ओर के कालम में दिए गए शब्दों को दाईं ओर के कॉलम में दिए गए नामों से मिलाइए।

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. डब्ल्यू डब्ल्यू रोस्टो | भुगतान-संतुलन संबंधी समस्याओं का समाधान |
| 2. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष | क्यूबा |
| 3. प्रेब्रिस्च | वेनेजुएला के राष्ट्रीय नेता |
| 4. फिडेल कास्त्रे | आधुनिकीकरण का सिद्धांत |
| 5. चावेज | आश्रित का सिद्धांत |



आपने क्या सीखा

आज संसार अनेक ऐसे राष्ट्रों में बँटा है, जो अपने मामलों में निर्णय लेने के लिए औपचारिक रूप से स्वतंत्र हैं। यूरोपीय देश अब अपने से कहीं बड़े और अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों पर शासन नहीं करते। सैकड़ों राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम, जिनमें से कुछ द्वितीय विश्वयुद्ध से पहले शुरू हुए, युद्ध के बाद सफल रहे। एक ओर जहाँ राष्ट्रों और 'राष्ट्रीय' अलगाववादी आंदोलनों (अन्य राष्ट्रों में शामिल होने की या अपने स्वयं के राष्ट्र बनाने के इच्छुक लोगों द्वारा चलाए गए) के बीच आक्रामकता जारी है, वहीं ऐसे टकरावों को न्यूनतम करने के लिए पारदेशीय संस्थाएं और संगठन भी मौजूद हैं। इनमें से कुछ संगठन पूर्ववर्ती उपनिवेशों और विश्व के अन्य गरीब क्षेत्रों के 'विकास' में सहायता करने के लिए स्थापित हुए थे। फिर भी, राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्रामों की शुरुआत के पचास से ज्यादा साल बाद भी पांच-छह राष्ट्र शेष सब राष्ट्रों की सम्मिलित धन-संपदा से भी ज्यादा धन-संपदा पर नियंत्रण रखते हैं : विश्व में असमान आर्थिक शक्ति के बारे में बहस भी जारी है।



आपकी टिप्पणियाँ



पाठान्त प्रश्न

1. 'पुरानी' आधुनिक क्रांतियों (अमेरिका और फ्रांस की) और 1917 की रूसी क्रांति ने बीसवीं शताब्दी के राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्रामों को किस प्रकार प्रभावित किया।
2. उपनिवेश-विरोधी संग्रामों के उन कुछ नेताओं के बारे में बताएं, जिन्होंने अपने औपनिवेशिक 'स्वामियों' के देश में रहकर कार्य किया?
3. कौन से उपनिवेश-विरोधी राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम दूसरे विश्वयुद्ध से प्रारंभ हुआ या उसमें से निकला?
4. यह कहना क्यों उचित है कि बीसवीं सदी की चीनी क्रांति इतिहास की 'महानतम क्रांति' रही है?
5. राष्ट्रीय विकास की कुछ प्रमुख (भिन्न) रणनीतियों का वर्णन करें?
6. वैश्विक व्यापार और विकास में समानता लाने के लिए कौन-सी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं आविष्कृत की गई हैं?



पाठगत प्रश्नों के उत्तर

26.1

1. ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा
2. उपनिवेशी जनता को गृही सेना में शामिल करने और युद्ध-उद्योगों में भागीदारी से उन लोगों को पूर्ण नागरिकता के अधिकार तथा राष्ट्रीय स्वाधीनता की मांग करने की प्रेरणा मिली।
3. अल्जीरिया, मलाया, अंगोला, मोजाम्बिक, वियतनाम

26.2

1. अफ्रीकी तानाशाह
2. इंडोनेशिया
3. भारत
4. 1945 में स्थापित

26.3

1. 1945 के बाद सोवियत संघ ने अनेक स्वाधीनता संग्रामों को मदद दी। अमेरिका ने कुछ राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्रामों का विरोध किया और कुछ को प्रोत्साहित किया। महा अक्तियों ने इस बात को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्रामों का समर्थन या विरोध किया कि इससे उनके विरोधियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
2. दक्षिण कोरिया, ताइवान, हांगकांग, सिंगापुर



आपकी टिप्पणियाँ

3. अफ्रीका और लैटिन अमेरिका

26.4

1. सोवियत संघ के साथ जापान, अमेरिका और चीनी लोकतांत्रिक गणराज्य के संबंध 1957 के बाद की तुलना में पहले बेहतर थे। चीनी लोकतांत्रिक गणराज्य के ग्रेट ब्रिटेन के साथ खराब संबंध थे, क्योंकि उसने हांगकांग पर कब्जा (1997 तक) किया हुआ था।
2. 1980 में सीसीपी का पिछले तीन दशकों की तुलना में राष्ट्रीय उद्योगों के एक छोटे हिस्से पर नियंत्रण था और उसने भारी विदेशी निवेश को आमंत्रित और प्राप्त भी किया।
3. चीनी लोकतांत्रिक राज्य ने अमेरिका के विरुद्ध वियतनाम की सहायता नहीं की, हालांकि समाजवादी आदर्शों के अनुसार उसे ऐसा करना चाहिए था।

26.5

1. आधुनिकीकरण का सिद्धांत
2. भुगतान-संतुलन संबंधी समस्याओं का निवारण
3. निर्भरता का सिद्धांत
4. क्यूबा
5. वेनेजुएला के राष्ट्रीय नेता

पाठान्त प्रश्नों के लिए संकेत

1. देखें पैरा 26.1
2. देखें पैरा 26.4
3. देखें पैरा 26.2, 26.4
4. देखें पैरा 26.5
5. देखें पैरा 26.6 उपपैरा 4 से 9
6. देखें पैरा 26.6 उपपैरा 1.2

शब्दावली

- वि-उपनिवेशीकरण - यह साम्राज्यवाद की उलटी प्रक्रिया है, जिसमें उपनिवेश राजनीतिक दृष्टि से स्वतंत्र राष्ट्र बन जाते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से वि-उपनिवेशीकरण सामान्यतः 1945-90 की अवधि को कहा जाता है।
- शीतयुद्ध - 1945 से 1990 तक की अवधि जब दो नई महाशक्तियों ने एक दूसरे से सीधे युद्ध (उष्ण युद्ध) न करके छदय युद्धों के माध्यम से एक दूसरे के



आपकी टिप्पणियाँ

गुटनिरपेक्ष आंदोलन
(एन ए एम नाम)

-

विस्तार का विरोध करने की कोशिश की। शीतयुद्ध के मुख्य संघर्ष थे— सोवियत संघ द्वारा वियतनामी राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम को सहायता पहुँचाना। और अमेरिका द्वारा सोवियत संघ के खिलाफ लड़ रहे अफगानी स्वतंत्रता सेनानियों की मदद करना।

1950 से पूर्ववर्ती उपनिवेशीकृत राष्ट्रों का एक संघ, जिसने 'महाशक्तियों' अमेरिका और सोवियत संघ पर नई निर्भरता से बचने का प्रयास किया। नाम राष्ट्रों में भारत, पाकिस्तान, मिस्र, क्यूबा एवं इंडोनेशिया शामिल है। गुटनिरपेक्षता की शपथ लेने के बावजूद कुछ राष्ट्र सैन्य सुरक्षा, व्यापार और आर्थिक विनिमय जैसे मामलों में किसी न किसी महाशक्ति पर निर्भर हो गए।

तीसरी दुनिया

-

'विकास' (आर्थिक आधुनिकीकरण) के जरूरतमंद पूर्ववर्ती औपनिवेशिक क्षेत्रों को दर्शाने के लिए 1950 के दशक के प्रारंभ में गढ़ा गया शब्द। पहली दुनिया यू0 के0, अमेरिका एवं कनाडा सहित धनी पूँजीवादी या गैर-समाजवादी राष्ट्रों को कहा जाता है। दूसरी दुनिया में (1990 तक) सोवियत संघ और उसका समाजवादी मार्ग अपनाने वाले अन्य यूरोपीय देश आते हैं, जैसे पोलैंड एवं बुलारिया।

विकास सहायता

-

धनी राष्ट्रों (या ऐसे राष्ट्रों के संघों) द्वारा गरीब देशों को उनके आर्थिक आधुनिकीकरण के लिए दिया जाने वाला धन या वित्तीय ऋण। शीतयुद्ध के दौरान महाशक्तियों अथवा उनके सहयोगी राष्ट्रों द्वारा विकास सहायता राशि का उपयोग पूर्ववर्ती उपनिवेशीकृत राष्ट्रों को अमेरिका या सोवियत संघ के पक्ष में करने के लिए किया गया।

आधुनिकीकरण का सिद्धांत -

अमेरिकी अर्थशास्त्री डब्ल्यू डब्ल्यू रोस्टो द्वारा 1950 के दशक में प्रतिपादित आर्थिक विकास का सिद्धांत। रोस्टो का मानना था कि आर्थिक विकास और आधुनिकीकरण में औद्योगिकीकरण शामिल होगा, लेकिन पूँजीवादी कृषि विकास के बाद। मोटे तौर पर ब्रिटेन, अमेरिका और जर्मनी ऐसे देश थे, जिनका तीसरी दुनिया के देशों ने अनुसरण किया।

बाजार का समाजवाद

-

चीनी लोकतांत्रिक गणराज्य के नेताओं द्वारा सन् 1980 से अपने विकास की मिश्रित या संयुक्त रणनीति को परिभाषित करने के लिए प्रयुक्त शब्द।



आपकी टिप्पणियाँ

पूरे देश में सशक्त केन्द्रीय (आर्थिक) आयोजना और संसाधनों (उत्पादन के साधनों) पर राष्ट्र के स्वामित्व के बजाय, जैसा कि 1980 से पहले था, विदेशी भागीदारों सहित पूँजीपतियों को अपनी निवेशकों के लिए लाभ कमाने की अनुमति होती है। विशेष 'मुक्त उद्यम क्षेत्रों' को मान्यता देकर चीनी राज्य उनमें पूँजीवाद को कार्य करने की अनुमति देते हैं।